भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1312
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी क्षेत्र

1312. श्री नव चरण माझीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने वाली पहलों के उद्देश्य क्या हैं और ये अपना लक्ष्य किस प्रकार पूरा करेंगी;

(ख) मयूरभंज जिले में लाभार्थियों को 3000 उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले मवेशियों के वितरण से स्थानीय दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आय पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम मयूरभंज में बच्चों में कुपोषण का प्रभावी ढंग से मुकाबला करे, अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मंत्रालय की यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है कि संपुष्ट दुग्ध पोषण गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों को पूरा करे और कुपोषण का मुकाबला करने में इसकी प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने दूध की खरीद-क्षमता को पांच लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर दस लाख लीटर प्रतिदिन करने के उद्देश्य से एक नया बाजार समर्थन कार्यक्रम शुरू किया है और मंत्रालय का किस प्रकार यह अनुमान है कि इससे ओडिशा, विशेषकर मयूरभंज में दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और किसानों की आय प्रभावित होगी, और

(च) बाजार सहायता कार्यक्रम और 37.45 करोड़ रुपये की उत्पादकता वृद्धि परियोजना का महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग महाराष्ट्र सहित देश भर में डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन जिसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देशी बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भाग ले रहा है और योजना के प्रारंभ से अब तक 101.58 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम के तहत अब तक 2 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 2.54 लाख एआई किए गए हैं और महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 1.22 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। आज तक 51.77 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 46.46 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ 4 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें जलगांव जिले के लिए 1.30 करोड़ रुपये शामिल हैं। जलगांव डेयरी संयंत्र प्रयोगशाला को सुदृढ़ किया गया है और जलगांव जिले में 121 डेयरी सहकारी समितियों को स्वचालित दूध संग्रह इकाई प्रदान की गई है।

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना है, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके। अब तक, महाराष्ट्र में 1268.72 करोड़ रुपये की ऋण राशि सहित 1856.85 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 30 डेयरी परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है।

(ख) मयूरभंज जिले में स्थानीय पशुओं की कम उत्पादकता उनकी आनुवंशिक संरचना में कमी के कारण है। जिले में स्थानीय पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 3,000 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं को शामिल किया गया है। इससे न केवल जिले में दूध का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण आय में भी वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए ओडिशा के मयूरभंज जिले में गिफ्टमिल्क कार्यक्रम आरंभ किया गया है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम कुछ चुनिंदा स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें करीब 1200 बच्चे हैं। गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन छात्रों को विटामिन ए और डी से भरपूर गुणवत्तायुक्त 200 मिलीलीटर फ्लेवर्ड दूध वितरित कर रहा है, जिसके कई फायदे हैं। कार्यक्रम के तहत दूध की आपूर्ति भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार की जाती है।

(ङ) जी हां। ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (ओएमएफईडी) और उनके घटक दूध संघ मिलकर प्रतिदिन करीब 5 लाख लीटर दूध खरीदते हैं। दूध की खरीद में वृद्धि को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने 3.9 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ब्रांड निर्माण, वितरण कवरेज वृद्धि और क्षमता निर्माण के लिए बाजार सहायता कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें एनडीडीबी अनुदान के रूप में 1.90 करोड़ रुपये और 1.41 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान कर रहा है।

(च) ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड द्वारा दूध खरीद बढ़ाने के लिए बाजार सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 37.45 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कार्यान्वित किया जा रहा उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम मयूरभंज जिले में बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए है। दोनों कार्यक्रम किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हैं।

महाराष्ट्र, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु दूध खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं में प्रतिभागी है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य में दूध उत्पादन वर्ष 2019-20 में 12.02 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 16.04 मिलियन टन हो गया है, जो 33.44% की वृद्धि है।

******